(b) No problems have arisen in the functioning.

(c) No further steps are required to be taken.

मोती बाग को म्युचुअल एंड एजुकेशन (विद्या निकेतन) सोसायटी को भूमि का आवंटन

4181. मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सभा की याचिका समिति की सिफारिशों के आधार पर नई दिल्ली के नानक पुरा में एक विद्यालय खोलने के लिए मोती बाग म्युचुअल एड एजुकेशन (विद्या निकेतन) सोसायटी को 1987 में एक भूखंड आवंटित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दिल्ली नगर निगम सोसायटी के भवन के नक्शे को इस आधार पर अनुमोदित नहीं कर रहा है कि मंत्रालय के भूमि और विकास अधिकारी को इस स्थान का आवंटन करने का प्राधिकार प्राप्त नहीं था; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है ताकि सोसायटी द्वारा दिया गया भवन का नक्शा बिना विलम्ब के अनुमोदित हो सके और विद्यालय सहज तथा सुचारु ढंग से शिक्षा प्रदान कर सके ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) यह सत्य है कि दिल्ली नगर निगम ने प्राइमरी स्कूल के निर्माण के लिए भवन नक्शा अनुमोदित नहीं किया है क्योंकि वे मानते हैं कि वह स्थल उनका है ।

(ग) इस बाबत दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों को दिसम्बर, 92 में सूचित किया गया था कि वह स्थान कभी भी दिल्ली नगर निगम को आवंटित नहीं किया गया था और इसलिए यह उनका नहीं है । उनसे मोती बाग म्युचुअल एंड एजुकेशन (विद्या-निकेतन) सोसायटी द्वारा प्रस्तुत नक्शा शीघ्र अनुमोदित करने का भी अनुरोध किया गया था । आयुक्त (दिल्ली नगर निगम) को पुनः कहा गया है कि वे उक्त सोसायटी द्वारा प्रस्तुत भवन नक्शों को शीघ्र मंजूरी दें और इस मंत्रालय को अवगत कराये ।

National Capital Region Plan

4182. SHRI V. NARAYANASAMY : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the National Capital Region Plan designed to contain population of the capital to the manageable limit of 112 lakhs by the year 2001 is far from complete as reported in the 'Indian Express' dated 27th March, 1994;

(b) if so, what steps have been taken to hasten the process; and

(c) whether Government propose to go ahead with the plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON) :
(a) to (c) NCR Planning Board has reported that there are still 7 years to go for the fulfilment of the aims and objective of NCR including the goal of containing the Delhi's population to a manageable limits as provided in Regional Plan-2001. As such, the question of either the planning or implementation process being fully complete at this stage does not arise. However keeping the aforesaid time-limit in view, VIII Plan investment programme has been substantially stepped up both in the Central Sector which is to be implemented by the Central Ministries and in the State Sector to be jointly implemented by the constituent States alongwith the NCR Planning Board.

Privatisation of DDA's Construction Activities

4183. SHRI SURESH KALMADI : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Delhi Development Authority has initiated the privatisation process of its construction activity;

(b) if so, what are the details of the steps taken in this direction so far; and

(c) what will be the future programme of the DDA in this sphere?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON) : (a) Yes, Sir. A proposal in this regard has been received from DDA.

(b) The proposal submitted by DDA envisages private sector involvement in the development of land and construction of houses on:

(i) Land acquired by the Delhi Development Authority, as well as.

(ii) Land assembled by the private developers. Both these broad models would be subject to the overall planning supervision of DDA.

(c) When the scheme is operative it is envisaged that the DDA will continue to be the nodal planning agency, which will offer acquired lands for development according to the Master Plan, monitor progress of all actual constructions, and oversee disposal of such construction according to policy of Government.